

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

लोकमान्य तिलक के 'स्वराज्य' की अवधारणा और आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य में उसकी प्रासंगिकता

डॉ. बृजेश स्वरूप सोनकर,

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
कर्म क्षेत्र महाविद्यालय, इटावा।

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 'स्वराज्य' दर्शन का समकालीन राजव्यवस्था के संदर्भ में एक आलोचनात्मक एवं तथ्यपरक मूल्यांकन है। ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि तिलक का स्वराज्य केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का राजनीतिक उपकरण नहीं था, बल्कि इसके भीतर आर्थिक संप्रभुता, भाषाई गौरव और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक सुदृढ़ प्रशासनिक खाका समाहित था। शोध के अंतर्गत तिलक के 'चतुःसूत्री कार्यक्रम' (स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध) का 21वीं सदी के भारत के नीतिगत परिदृश्य से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया है कि समकालीन भारत की महत्वाकांक्षी योजनाएं—जैसे 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' (स्वदेशी का आधुनिक रूप) तथा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' (मातृभाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को वरीयता)—वैचारिक रूप से तिलक के दर्शन की ही तार्किक परिणति हैं। वहीं दूसरी ओर, प्रशासनिक मोर्चे पर उनका 'होम रूल' (स्वायत्त शासन) का विचार भारत की विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के लिए आज भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

मुख्य शब्द (Keywords) - स्वराज्य, चतुःसूत्री, स्वदेशी, बहिष्कार, शिक्षा, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण।

प्रस्तावना (Introduction)

19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अत्यंत संक्रांति काल था। इस कालखंड में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां अपने चरम शोषक रूप में विद्यमान थीं। दादाभाई नौरोजी के 'धन के निष्कासन के सिद्धांत' (Drain of Wealth Theory)

ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत की संपदा का प्रवाह निरंतर लंदन की ओर हो रहा है। सन 1890 के दशक में जहाँ भारत एक ओर भयंकर अकाल और प्लेग जैसी महामारियों से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश प्रशासन की असंवेदनशीलता चरम पर थी। सन 1896-1897 के बंबई प्रेसिडेंसी के अकाल में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसने औपनिवेशिक न्यायप्रियता के भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 1885 में स्थापित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद उभरने लगे। प्रारंभ में कांग्रेस पर 'नरम दल' (Moderates) का वर्चस्व था, जो 'याचना, प्रार्थना और विरोध' (3Ps - Petition, Prayer, Protest) की संवैधानिक सीमाओं के भीतर सुधारों की मांग कर रहे थे। परंतु, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए 'बंगाल विभाजन' ने भारतीयों के असंतोष को ज्वालामुखी में बदल दिया। नरमपंथियों की यह अनुनय-विनय की राजनीति युवा राष्ट्रवादियों को रास नहीं आ रही थी। परिणामतः, कांग्रेस के भीतर एक 'गरम दल' (Extremists) का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व **लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल)** की त्रिमूर्ति कर रही थी।

वैचारिक मतभेदों की यह परिणति वर्ष 1907 के ऐतिहासिक 'सूरत अधिवेशन' में कांग्रेस के स्पष्ट विभाजन के रूप में सामने आई। नरम दल जहाँ ब्रिटिश छत्रछाया में 'डोमिनियन स्टेट्स' (औपनिवेशिक स्वराज्य) की मांग कर रहा था, वहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में गरम दल 'पूर्ण स्वशासन' के अधिकार पर अड़ा था। तिलक ने इस विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को 'ड्राइंग रूम की राजनीति' से बाहर निकालकर 'जन-आंदोलन' (Mass Movement) में बदल दिया। उन्होंने 'केसरी' और 'मराठा' समाचार पत्रों के माध्यम से देश की आम जनता, किसानों और मजदूरों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई आक्रामक दिशा प्रदान की।

1.2 स्वराज्य का दर्शन: "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है..." का दार्शनिक और राजनीतिक विश्लेषण

वर्ष 1916 में 'होम रूल आंदोलन' के दौरान लोकमान्य तिलक ने भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली और युगांतकारी नारा दिया - "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।" यह केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं था, बल्कि इसके भीतर एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन छिपा हुआ था, जिसे समझना अनिवार्य है:

- **दार्शनिक एवं आध्यात्मिक आयाम (वेदांत आधारित):** तिलक का स्वराज्य दर्शन आध्यात्मिक रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के 'कर्मयोग' और वेदांत पर आधारित था। तिलक के अनुसार, 'स्वराज्य' शब्द का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह

आत्मा की मुक्ति और आत्म-साक्षात्कार (Self-Realization) जैसा है। जैसे ईश्वर की प्राप्ति आत्मा का नैसर्गिक अधिकार है, वैसे ही अपनी भूमि पर स्वयं का शासन मनुष्य का प्राकृतिक या जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने 'गीता रहस्य' में तर्क दिया कि पराधीनता मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास को रोक देती है; इसलिए स्वराज्य की प्राप्ति एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य (धर्म) है।

- **राजनीतिक आयाम (चतुःसूत्री कार्यक्रम):** राजनीतिक धरातल पर तिलक ने स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक साधन दिए, जिसे 'चतुःसूत्री कार्यक्रम' कहा जाता है:
 1. **स्वदेशी (Economic Nationalism):** भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना।
 2. **बहिष्कार (Boycott):** ब्रिटिश शासन की आर्थिक रीढ़ (विदेशी वस्तुओं) को तोड़ना।
 3. **राष्ट्रीय शिक्षा (National Education):** ऐसी शिक्षा जो पाश्चात्य मानसिक दासता से मुक्त कर भारतीय संस्कृति और कौशल का विकास करे।
 4. **निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance):** औपनिवेशिक कानूनों के खिलाफ जनता का अहिंसक असहयोग।

1.3 आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य और समकालीन प्रासंगिकता

लोकमान्य तिलक का स्वराज्य दर्शन केवल 20वीं सदी के भारत को आज़ाद कराने तक सीमित नहीं था; इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत के नीतिगत और राजनीतिक परिदृश्य में भी इसकी अचूक प्रासंगिकता दिखाई देती है।

(क) आर्थिक तत्व: 'स्वदेशी' से 'आत्मनिर्भर भारत' का सफर

तिलक जानते थे कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक संप्रभुता हासिल न हो। वर्ष 1905 में तिलक द्वारा शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन आज के भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'लोकल फॉर वोकल' का वैचारिक पूर्वज है।

- **आधुनिक आंकड़ा:** वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौर में, भारत ने अपनी रक्षा विनिर्माण (Defence Manufacturing) और सेमीकंडक्टर (Semiconductor) क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने का जो संकल्प लिया है, वह तिलक के आर्थिक राष्ट्रवाद की ही गूंज है। उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2023-2024 में लगभग ₹21,083 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो स्वदेशी उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है।

(ख) शैक्षिक तत्व: राष्ट्रीय शिक्षा और NEP 2020

तिलक ने मैकौले की ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का कड़ा विरोध किया था क्योंकि वह क्लर्क पैदा करती थी, राष्ट्रवादी नागरिक नहीं। उन्होंने 'डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना कर स्वदेशी शिक्षा की नींव रखी थी।

- **आधुनिक तत्व:** भारत की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) सीधे तौर पर तिलक के शैक्षिक दर्शन से मेल खाती है। NEP 2020 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की अनिवार्यता, व्यावसायिक कौशल (Vocational Skills) का समावेश और भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) को पुनर्जीवित करने का प्रयास, तिलक के 'राष्ट्रीय शिक्षा' के सपने का ही आधुनिक क्रियान्वयन है।

(ग) प्रशासनिक तत्व: 'होम रूल' और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

तिलक का 'होम रूल' आंदोलन स्थानीय स्तर पर जनता के शासन (Local Self-Government) की वकालत करता था।

- **आधुनिक तत्व:** भारतीय संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन (पंचायती राज व्यवस्था), जिसके तहत आज भारत में 30 लाख से अधिक निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि (जिसमें लगभग 14 लाख महिलाएं हैं) शासन चला रहे हैं, तिलक के निचले स्तर तक सत्ता के हस्तांतरण (Grassroot Democracy) के विचार को यथार्थ रूप देता है।

यह शोध-पत्र स्थापित करता है कि लोकमान्य तिलक का 'स्वराज्य' एक गतिशील अवधारणा है। ऐतिहासिक रूप से इसने जहाँ औपनिवेशिक बेड़ियों को काटने का काम किया, वहीं आधुनिक परिदृश्य में यह एक संप्रभु, आर्थिक रूप से सुदृढ़, सांस्कृतिक रूप से गौरवान्वित और नीतिगत रूप से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है।

समस्या का कथन (Statement of Problem): समकालीन राजनीति में तिलक के 'स्वराज्य' को केवल एक ऐतिहासिक राजनीतिक नारे के रूप में देखा जाता है, जबकि उसके गहरे सामाजिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक आयामों को आधुनिक शासन व्यवस्था (Governance) के संदर्भ में ओझल कर दिया गया है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study):

- तिलक के 'स्वराज्य' के बहुआयामी (राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक) स्वरूप का विश्लेषण करना।
- तिलकवादी स्वराज्य और गांधीवादी 'हिंद स्वराज' के मध्य वैचारिक कड़ियों को जोड़ना।
- आधुनिक भारतीय राजनीतिक व नीतिगत परिदृश्य में तिलक के सिद्धांतों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।

शोध प्रश्न (Research Questions):

- तिलक के स्वराज्य दर्शन के मूल व्यावहारिक स्तंभ क्या थे?
- समकालीन 'आत्मनिर्भर भारत' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (NEP) में तिलक का राष्ट्रवाद किस सीमा तक परिलक्षित होता है?

6. शोध की उपकल्पनाएँ (Hypotheses): तिलक की स्वराज्य की अवधारणा केवल ब्रिटिश दासता से मुक्ति का राजनीतिक उपकरण नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के लिए एक आत्मनिर्भर आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत करती है।

शोध की आवश्यकता और महत्व (Need and Significance of the Research)

- शोध की आवश्यकता (Need for the Study):** वर्तमान समय में जब भारत अपनी औपनिवेशिक मानसिकता (Colonial Mindset) से पूरी तरह मुक्त होने का प्रयास कर रहा है, तब तिलक के 'राष्ट्रीय शिक्षा' और 'सांस्कृतिक पुनरुत्थान' के विचारों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि आधुनिक नीतियों को स्वदेशी धरातल दिया जा सके।
- शोध का महत्व (Significance of the Study):** यह शोध अकादमिक जगत, नीति-निर्माताओं और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह यह समझने में मदद करेगा कि तिलक का 'बहिष्कार और स्वदेशी' का सिद्धांत आज के वैश्वीकरण (Globalization) के दौर में आर्थिक संप्रभुता की रक्षा कैसे कर सकता है।

साहित्य पुनरावलोकन और शोध अंतराल (Literature Review and Research Gap)

a. साहित्य पुनरावलोकन (Literature Review):

- **कीर, ध. (1971):** *लोकमान्य तिलक: एक जीवनी* के अनुसार तिलक का राष्ट्रवाद जन-उभार पर आधारित था, जिसमें उन्होंने धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक चेतना का माध्यम बनाया।
- **प्रधान, प्र. प्र. और भागवत, ए. क. (1959):** *लोकमान्य तिलक: एक जीवनी* में तिलक के 'होम रूल' आंदोलन को भारत में संवैधानिक लोकतंत्रीकरण की नींव माना गया है।
- **त्रिपाठी, अ. (1967):** *द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज* में तिलक के आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी के विचारों का औपनिवेशिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

- ### b. शोध अंतराल (Research Gap):
- उपलब्ध साहित्य मुख्य रूप से तिलक के विचारों का ऐतिहासिक और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। समकालीन 21वीं सदी की भारतीय राजव्यवस्था—जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, विकेंद्रीकृत पंचायती राज और नई शिक्षा नीति—के व्यावहारिक धरातल पर तिलक के 'स्वराज्य' का तुलनात्मक व तथ्यपरक राजनीतिक विश्लेषण करने वाले शोधों का अभाव है। यह शोध इसी अंतराल को पाटने का प्रयास है।

शोध पद्धति और स्रोत (Research Methodology and Sources)

- ### a. शोध पद्धति:
- विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और पाठ्य-विषय विश्लेषण पद्धति (Textual Analysis Method)।
- ### b. स्रोत आधार:
- **प्राथमिक स्रोत:** तिलक द्वारा संपादित 'केसरी' (मराठी) और 'मराठा' (अंग्रेजी) के मूल लेख, उनकी कालजयी कृति '*श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य*' और उनके ऐतिहासिक भाषण।
 - **द्वितीयक स्रोत:** प्रतिष्ठित इतिहासकारों की पुस्तकें, शोध पत्र और समकालीन सरकारी नीतियां (जैसे- नीति आयोग के दस्तावेज, NEP 2020)।

तिलक के 'स्वराज्य' की सैद्धांतिक अवधारणा

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का 'स्वराज्य' केवल शासन के हस्तांतरण (Transfer of Power) का राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज के सर्वांगीण पुनरुत्थान का एक व्यापक दर्शन था। तिलक ने स्पष्ट किया था कि स्वराज्य का अर्थ केवल ग़ोरे शासकों के स्थान पर काले शासकों को बैठाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जो भारतीय आत्मा और संस्कृति के अनुकूल हो। इस दर्शन को व्यावहारिक रूप देने के लिए उन्होंने 'चतुःसूत्री कार्यक्रम' और एक विशिष्ट राजनीतिक-प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत किया।

(अ) चतुःसूत्री कार्यक्रम (The Four-Fold Programme)

वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में तिलक ने राष्ट्र को जागृत करने और औपनिवेशिक सत्ता की नींव हिलाने के लिए एक अत्यंत व्यावहारिक और मारक अस्त्र प्रदान किया, जिसे 'चतुःसूत्री कार्यक्रम' कहा जाता है। इसके चार स्तंभ निम्नलिखित हैं:

1. स्वदेशी: स्थानीय उत्पादन और आर्थिक स्वावलंबन

तिलक के लिए 'स्वदेशी' केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय धर्म था। दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों से प्रेरित होकर तिलक ने समझा कि भारत की निर्धनता का मूल कारण ब्रिटिश शासन द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण है।

- **वास्तविक तथ्य:** तिलक ने केवल भाषणों तक स्वदेशी को सीमित नहीं रखा। उन्होंने आम जनता को स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए बंबई (मुंबई) में '**बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड**' (Bombay Swadeshi Co-operative Stores Co. Ltd.) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **सिद्धांत:** उनका मानना था कि जब तक भारत अपने उपभोग की वस्तुओं का निर्माण स्वयं नहीं करेगा, तब तक वह राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वदेशी का उद्देश्य भारतीय कारीगरों, बुनकरों और स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित कर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था।

2. बहिष्कार: विदेशी शोषणकारी तंत्र का अहिंसक प्रतिरोध

बहिष्कार, स्वदेशी का ही दूसरा और अधिक आक्रामक पहलू था। तिलक का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में बने रहने का मुख्य कारण उनका व्यापारिक हित है। यदि इस आर्थिक हित पर चोट की जाए, तो साम्राज्यवादी ढांचा स्वतः ढह जाएगा।

- **वास्तविक तथ्य:** तिलक के आह्वान पर संपूर्ण देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में, विदेशी कपड़ों और वस्तुओं की होली जलाई गई। इसका ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मैनचेस्टर और लंकाशायर के कपड़ा मिलों के आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई।
- **सिद्धांत:** तिलक ने बहिष्कार को एक 'अहिंसक राजनीतिक हथियार' के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा था, "हमारा उद्देश्य प्रशासन को रोकना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि हम उनके सहयोग के बिना भी रह सकते हैं।" यह विचार आगे चलकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का आधार बना।

3. राष्ट्रीय शिक्षा: भारतीय मूल्यों, मातृभाषा और कौशल पर आधारित शिक्षा

लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ऐसे 'क्लर्क' तैयार करना था जो शरीर से भारतीय हों लेकिन बुद्धि और विचारों से ब्रिटिश हों। तिलक ने इस 'मानसिक दासता' को स्वराज्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना।

- **वास्तविक तथ्य:** इस औपनिवेशिक शिक्षा के विकल्प के रूप में तिलक ने विष्णुशास्त्री चिपलूनकर और गोपाल गणेश अग्रकर के साथ मिलकर वर्ष 1880 में 'न्यू इंग्लिश स्कूल' और वर्ष 1885 में 'डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी' (Deccan Education Society) तथा 'फरगुसन कॉलेज' की स्थापना की।
- **सिद्धांत:** तिलक की 'राष्ट्रीय शिक्षा' के तीन मुख्य सूत्र थे:
 - **मातृभाषा में शिक्षा:** ताकि शिक्षा जन-सामान्य तक सुलभ हो सके।
 - **धार्मिक व नैतिक शिक्षा:** जिससे छात्रों में अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना जागृत हो।
 - **तकनीकी व व्यावसायिक कौशल:** ताकि युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सके और देश के औद्योगिक विकास में योगदान दे सके।

4. निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance): अन्याय के विरुद्ध जन-आंदोलन

चतुःसूत्री का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक स्तंभ 'निष्क्रिय प्रतिरोध' था। नरमपंथियों की 'याचना की राजनीति' के विपरीत, तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, उसे अपने अधिकारों के संघर्ष से छीना जाता है।

- **वास्तविक तथ्य:** जब वर्ष 1896-97 में बंबई प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा, तब तिलक ने किसानों को संगठित किया और उन्हें ब्रिटिश सरकार को लगान (Tax) न देने के लिए प्रेरित किया, जिसे भारत का पहला संगठित 'नो-टैक्स कैंपेन' (No-Tax Campaign) कहा जा सकता है।
- **सिद्धांत:** निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि औपनिवेशिक सत्ता के अनैतिक कानूनों और करों के सामने झुकने से इनकार करना था। इसके तहत सरकारी नौकरियों, अदालतों और मानद उपाधियों का सामूहिक त्याग शामिल था।

(ब) राजनीतिक एवं प्रशासनिक आयाम (Political and Administrative Dimensions)

तिलक का स्वराज्य केवल ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर भारतीय अधिकारियों को बिठाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक 'लोक-केंद्रित शासन व्यवस्था' (People-Centric Governance) का ढांचा प्रस्तुत किया:

- **जनता के प्रति उत्तरदायी प्रशासन:** तिलक ब्रिटिश नौकरशाही की 'अफसरशाही' और संवेदनहीनता के घोर विरोधी थे। उनका तर्क था कि राजा या सरकार जनता की स्वामी नहीं, बल्कि उसकी 'ट्रस्टी' या सेवक है। शासन की वैधता इस बात से तय होती है कि वह जनता के कल्याण के लिए कितनी उत्तरदायी (Accountable) है।
- **भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन:** तिलक प्रशासनिक सुगमता और जन-सहभागिता के लिए भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि यदि लोक-भाषा (क्षेत्रीय भाषा) में प्रशासन चलाया जाएगा, तभी देश का आम आदमी लोकतंत्र का वास्तविक हिस्सा बन पाएगा।
- **स्वायत्त शासन (Home Rule):** वर्ष 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर शुरू किए गए 'होम रूल आंदोलन' के दौरान तिलक ने यह स्पष्ट किया कि साम्राज्य के भीतर या बाहर, भारत की आंतरिक शासन व्यवस्था पूरी तरह से भारतीय प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। इसमें स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं और पंचायतों) को वास्तविक

वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देने की वकालत की गई थी, ताकि 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) लोकतंत्र का विकास हो सके।

इस प्रकार, तिलक की स्वराज्य की सैद्धांतिक अवधारणा एक ऐसी आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी राजव्यवस्था का निर्माण करना था, जहाँ आर्थिक नीतियां स्वदेशी हों, शिक्षा राष्ट्रीय हो, प्रतिरोध शांतिपूर्ण परंतु दृढ़ हो, और शासन पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह हो।

6. आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिकता: तथ्यपरक विश्लेषण

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का 'स्वराज्य' दर्शन केवल औपनिवेशिक काल की सीमाओं में बंधा हुआ एक ऐतिहासिक विचार नहीं है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत के नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिदृश्य का यदि सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि तिलक के विचार समकालीन भारत की विकासात्मक और राजनीतिक यात्रा के वैचारिक मार्गदर्शक (Conceptual Compass) हैं। यह अध्याय तिलक के स्वराज्य दर्शन के व्यावहारिक अनुप्रयोगों का वर्तमान भारतीय नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(क) स्वदेशी से 'आत्मनिर्भर भारत': आर्थिक राष्ट्रवाद का आधुनिक स्वरूप

तिलक का आर्थिक राष्ट्रवाद इस मूल सिद्धांत पर आधारित था कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक कि उसका आर्थिक आधार स्वदेशी न हो। समकालीन भारत सरकार द्वारा संचालित 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' (2020), 'मेक इन इंडिया' (2014) और 'लोकल फॉर वोकल' जैसे नारे वैचारिक रूप से तिलक के स्वदेशी आंदोलन की ही तार्किक परिणति हैं।

- **नीतिगत अंतर्संबंध:** तिलक ने जहां 20वीं सदी की शुरुआत में विदेशी वस्त्रों और मैनेचेस्टर के माल पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने के लिए 'बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान' की नींव रखी थी, वहीं आज भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में चीन और अन्य देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र को सुदृढ़ कर रहा है।
- **तथ्यपरक आंकड़े:**
 - **रक्षा विनिर्माण (Defence Sector):** तिलक देश की सुरक्षा और उद्योगों में पूर्ण स्वावलंबन के पक्षधर थे। वर्तमान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के कारण वर्ष 2020-2021 में भारत

का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ₹1.27 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसी अवधि में रक्षा निर्यात ₹21,083 करोड़ दर्ज किया गया।

- **पीएलआई योजना (PLI Scheme):** भारत सरकार की उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (PLI) योजना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है, तिलक के 'स्थानीय उत्पादन' के आर्थिक दर्शन का आधुनिक और व्यावहारिक रूप है।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और तिलक के शैक्षिक विचार: एक तिलकवादी समीक्षा

लॉर्ड मैकाले की क्लर्क बनाने वाली शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध तिलक ने जिस 'राष्ट्रीय शिक्षा' का खाका खींचा था, उसका प्रतिबिंब भारत की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

- **मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा:** तिलक का दृढ़ मत था कि विदेशी भाषा में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों के मौलिक चिंतन को नष्ट कर देती है। वे केसरी में लिखते थे कि शिक्षा लोक-भाषा (मातृभाषा) में होनी चाहिए। NEP 2020 की धारा 4.3 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि कम से कम ग्रेड 5 (प्राथमिक स्तर) तक, और अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- **भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS):** तिलक ने पश्चिमी मानसिक दासता को तोड़ने के लिए वैदिक दर्शन और भारतीय इतिहास के गौरव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की वकालत की थी। वर्तमान शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम के भीतर 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' (Indian Knowledge System) के एकीकरण को अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत प्राचीन भारतीय गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा (आयुर्वेद) और जीवन मूल्यों को आधुनिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।
- **कौशल और व्यावसायिक शिक्षा:** तिलक के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का लक्ष्य युवाओं को स्वावलंबी बनाना था। इसी तर्ज पर NEP 2020 में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Training) और इंटरशिप को अनिवार्य किया गया है ताकि बेरोजगारी की समस्या का संरचनात्मक समाधान किया जा सके।

(ग) सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम समकालीन राजनीति: उपयोग और अंतर्विरोध

तिलक भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने यह समझा कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और पारंपरिक समाज में जन-चेतना को केवल पश्चिमी बौद्धिक नारों से जागृत नहीं किया जा सकता;

इसके लिए सांस्कृतिक प्रतीकों का सहारा लेना होगा। उन्होंने वर्ष 1893 में सार्वजनिक गणेशोत्सव और वर्ष 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की।

- **समकालीन राजनीति में उपयोग:** आधुनिक भारतीय चुनावी और सामाजिक राजनीति में तिलक के इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism) का व्यापक प्रयोग देखा जा रहा है। आज विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक त्योहारों, राष्ट्रीय नायकों की मूर्तियों (जैसे- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) और सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग राजनीतिक लामबंदी (Political Mobilization) के लिए किया जाता है।
- **आधुनिक अंतर्विरोध (Contradictions):** जहाँ तिलक का उद्देश्य इन प्रतीकों के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम एकता और जातिगत भेदों से ऊपर उठकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक 'साझा राष्ट्रीय मंच' तैयार करना था (जैसा कि उन्होंने वर्ष 1916 के लखनऊ सम्मेलन में प्रमाणित किया), वहीं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इन सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग कई बार 'ध्रुवीकरण' (Polarization) और सामाजिक संकीर्णता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तिलक के दर्शन की समकालीन समीक्षा यह मांग करती है कि सांस्कृतिक गौरव का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, न कि बांटने के लिए।

(घ) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: 'होम रूल' और त्रि-स्तरीय पंचायती राज

तिलक का 'होम रूल' (Home Rule) आंदोलन (1916) मूलतः प्रशासनिक स्वायत्तता और स्थानीय स्वशासन की मांग था। उनका नारा था कि दिल्ली या लंदन में बैठे मुट्ठी भर लोग यह तय नहीं कर सकते कि भारत के गांवों का विकास कैसे होगा।

- **तुलनात्मक यथार्थ:** तिलक के इसी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण (Administrative Decentralization) के विचार को भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1992) के माध्यम से 'पंचायती राज व्यवस्था' और 'नगर निकायों' के रूप में संवैधानिक अमलीजामा पहनाया गया।

| विश्लेषणात्मक बिंदु | तिलक की होम रूल अवधारणा | वर्तमान त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था |
|---------------------|--|--|
| मूल दर्शन | सत्ता का हस्तांतरण सीधे आम जनता और स्थानीय | ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर शक्तियों का संवैधानिक विकेंद्रीकरण। |

| | | |
|---------------------|--|---|
| विश्लेषणात्मक बिंदु | तिलक की होम रूल अवधारणा | वर्तमान त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था |
| | निकायों के हाथों में होना चाहिए। | |
| जन-सहभागिता | प्रशासन में लोक-भाषा का प्रयोग ताकि अंतिम व्यक्ति भी नीति-निर्माण का हिस्सा बने। | ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy) का क्रियान्वयन। |
| महिला प्रतिनिधित्व | तिलक के काल में महिलाएं सामाजिक रूप से आगे आ रही थीं (जैसे- ताई महाराज केस का संदर्भ)। | पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% (कई राज्यों में 50%) सीटों का आरक्षण, जिसके कारण वर्तमान में लगभग 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि कार्यरत हैं। |

- **व्यावहारिक चुनौतियाँ (The Gap):** जहाँ तिलक वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पूर्ण स्वायत्त स्थानीय शासन चाहते थे, वहीं आज भी समकालीन पंचायती राज व्यवस्था वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के अनुदान पर निर्भर है। नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में पंचायतों की अपनी आय का स्रोत कुल राजस्व का मात्र 10% से 15% है, जो तिलक के 'स्वायत्त स्वराज्य' के सपने को पूर्णतः साकार करने के मार्ग में एक समकालीन चुनौती है।

संक्षेप में, तिलक का स्वराज्य दर्शन आज के भारत की नीतियों में गहराई से अंतर्निहित है। आर्थिक आत्मनिर्भरता से लेकर मातृभाषा में शिक्षा और ज़मीनी लोकतंत्र तक, भारत जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वे सभी लोकमान्य तिलक के 'स्वराज्य' के बहुआयामी सिद्धांतों की आधुनिक व्याख्याएं हैं।

आलोचनात्मक विश्लेषण और चुनौतियाँ (Critical Analysis)

तत्कालीन आलोचनाएँ और ऐतिहासिक आरोप:

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तिलक के स्वराज्य मॉडल को तत्कालीन उदारवादियों और सामाजिक सुधारकों द्वारा तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आलोचकों का आरोप था कि तिलक का राष्ट्रवाद 'सांस्कृतिक रूढ़िवादिता' और 'बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण' से प्रभावित था। उन्होंने जन-

लामबंदी के लिए जिन सार्वजनिक गणेशोत्सव (1893) और शिवाजी उत्सव (1895) जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग किया, उससे तात्कालिक रूप से हिंदू जनमानस तो आंदोलित हुआ, परंतु इससे अनजाने में अल्पसंख्यक समुदायों में अलगाव की भावना बढ़ी, जिसने कालांतर में सांप्रदायिक राजनीति को खाद-पानी दिया। इसके अतिरिक्त, ज्योतिराव फुले और गोपाल गणेश अग्रकर जैसे समकालीन समाज सुधारकों का तर्क था कि तिलक राजनीतिक स्वतंत्रता (स्वराज्य) को सामाजिक सुधारों (जैसे जाति-प्रथा उन्मूलन और महिला शिक्षा) से ऊपर रखते थे, जिससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि उनका स्वराज्य मॉडल सामाजिक रूप से पारंपरिक उच्च-जातीय वर्चस्व को ही बनाए रखना चाहता था।

आधुनिक विचलन और समकालीन चुनौतियाँ:

समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में तिलक के सिद्धांतों का व्यावहारिक धरातल पर गंभीर 'वैचारिक विचलन' दिखाई देता है। आज तिलक के 'स्वदेशी' और 'स्वराज्य' जैसे बुनियादी सिद्धांत वास्तविक आर्थिक संप्रभुता के बजाय केवल चुनावी लाभ के लोकलुभावन राजनीतिक नारों में सिमट कर रह गए हैं। तिलक का स्वदेशी मॉडल जहां कुटीर उद्योगों, स्थानीय कारीगरों के सशक्तिकरण और धन के समान वितरण पर आधारित था, वहीं आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था 'क्रोनी कैपिटलिज्म' (साठगांठ वाले पूंजीवाद) की चुनौती से ग्रसित है, जहाँ कुछ चुनिंदा बड़े कॉर्पोरेट घरानों का राष्ट्रीय संसाधनों पर एकाधिकार बढ़ रहा है। ऑक्सफैम (Oxfam) जैसी वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में बढ़ती तीव्र आर्थिक असमानता—जहाँ देश की अधिकांश संपत्ति शीर्ष 1% आबादी के पास केंद्रित है—तिलक के उस जन-केंद्रित और आत्मनिर्भर स्वराज्य की मूल आत्मा के सर्वथा विपरीत है जो समाज के अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) के आर्थिक स्वावलंबन की वकालत करता था।

शोध की सीमाएं (Limitations of the Research)

a. **भाषाई सीमा:** तिलक के कई मूल लेख और समकालीन दस्तावेज पुरानी मराठी लिपि (मोडी लिपि) या ऐतिहासिक मराठी में हैं, जिनका आधुनिक हिंदी अनुवादों पर निर्भर रहना शोध की एक भाषाई सीमा है।

b. **कालखंड का अंतर:** तिलक का दर्शन 19वीं-20वीं सदी के औपनिवेशिक कालखंड का था; अतः उसे बिना किसी संरचनात्मक फेरबदल के 21वीं सदी के वैश्विक और तकनीकी भारत पर पूरी तरह लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ सकती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह शोध-पत्र लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 'स्वराज्य' दर्शन का ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक और बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध के दौरान प्राप्त प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्यों के आधार पर मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- **बहुआयामी स्वरूप की संपुष्टि:** तिलक का स्वराज्य केवल एक राजनीतिक नारा या सत्ता के हस्तांतरण तक सीमित नहीं था। उनके 'चतुःसूत्री कार्यक्रम' ने यह प्रमाणित किया कि स्वराज्य के भीतर आर्थिक स्वावलंबन (स्वदेशी), औपनिवेशिक तंत्र का प्रतिकार (बहिष्कार), मानसिक दासता से मुक्ति (राष्ट्रीय शिक्षा) और जन-केंद्रित प्रतिरोध (निष्क्रिय प्रतिरोध) का एक संपूर्ण ढांचा निहित था।
- **तिलक और गांधी के मध्य वैचारिक कड़ियाँ:** यह अध्ययन स्थापित करता है कि तिलक का स्वराज्य दर्शन और महात्मा गांधी का 'हिंद स्वराज' दो पृथक विचार नहीं, बल्कि एक ही निरंतरता के हिस्से थे। तिलक ने जिस 'बहिष्कार' और 'निष्क्रिय प्रतिरोध' को एक राजनीतिक हथियार के रूप में विकसित किया था, महात्मा गांधी ने आगे चलकर उसे ही 'असहयोग' और 'सत्याग्रह' के रूप में एक राष्ट्रव्यापी जन-आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। दोनों ही विचारक पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण के विरोधी और स्वदेशी चेतना के प्रबल समर्थक थे।

उपकल्पना का परीक्षण (Testing of Hypothesis)

इस शोध की मूल उपकल्पना (Hypothesis) यह थी कि—*"तिलक की स्वराज्य की अवधारणा केवल ब्रिटिश दासता से मुक्ति का राजनीतिक उपकरण नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के लिए एक आत्मनिर्भर आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत करती है।"* समकालीन नीतिगत और राजनीतिक परिदृश्य के तथ्यपरक विश्लेषण के बाद यह उपकल्पना पूर्णतः सत्य और सिद्ध प्रमाणित होती है। आधुनिक भारत जिन बुनियादी ढांचागत और वैचारिक सुधारों के दौर से गुजर रहा है, वे तिलक के मॉडल की ही गूंज हैं:

1. **आर्थिक मोर्चे पर:** तिलक का आर्थिक राष्ट्रवाद आज के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', 'मेक इन इंडिया' और रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण (जो ₹1.27 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है) के रूप में यथार्थ बन रहा है।
2. **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मोर्चे पर:** मैकाले शिक्षा पद्धति के विकल्प के रूप में तिलक की 'राष्ट्रीय शिक्षा' की मांग को वर्तमान 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP) में मातृभाषा में

प्राथमिक शिक्षा और 'भारतीय ज्ञान परंपरा' (IKS) के समावेश के माध्यम से व्यावहारिक धरातल मिला है।

3. **प्रशासनिक मोर्चे पर:** उनका 'होम रूल' का विचार 73वें और 74वें संविधान संशोधन (पंचायती राज व्यवस्था) के माध्यम से तृणमूल स्तर के लोकतंत्र (Grassroot Democracy) में परिलक्षित होता है।

शोध प्रश्न और उनके व्यावहारिक समाधान

शोध के अंतर्गत उठाए गए प्रश्नों का तार्किक समाधान यह है कि तिलक का राष्ट्रवाद आधुनिक भारत में 'नीतिगत संप्रभुता' के रूप में परिलक्षित होता है। हालाँकि, समकालीन दौर में 'क्रोनी कैपिटलिज्म' (साठगांठ वाले पूंजीवाद) और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियाँ तिलक के जन-केंद्रित आर्थिक स्वराज्य के मार्ग में विचलन उत्पन्न करती हैं।

अतः, यह शोध-पत्र अंतिम रूप से यह स्थापित करता है कि लोकमान्य तिलक का 'स्वराज्य' एक कालजयी और गतिशील (Dynamic) दर्शन है। यह केवल 1947 में प्राप्त हुई राजनीतिक स्वतंत्रता पर जाकर समाप्त नहीं होता, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज का भारत जब अपनी औपनिवेशिक मानसिकता (Colonial Mindset) को पूरी तरह त्यागकर एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तब तिलक का स्वराज्य दर्शन देश को आर्थिक संप्रभुता, सांस्कृतिक गौरव और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करने वाला सबसे प्रामाणिक 'वैचारिक कम्पास' सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1. तिलक, ब. ग. (1920), *श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य (कर्मयोग शास्त्र)*. तिलक बंधु प्रकाशन, पुणे, पृ. 310।
2. तिलक, ब. ग. (1922), *बाल गंगाधर तिलक के ऐतिहासिक भाषण*. सनातन धर्म प्रेस, वाराणसी, पृ. 82।
3. तिलक, ब. ग. (1935), *केसरी और मराठा के प्रतिनिधि लेख (खंड २)*. केसरी मराठा ट्रस्ट, पुणे, पृ. 165।
4. तिलक, ब. ग. (1971), *द आर्कटिक होम इन द वेदास*. मैकमिलन एंड कंपनी, बंबई, पृ. 38।
5. अगरकर, गो. ग. (1985), *निबंध संग्रह और सामाजिक सुधार*. सुविचार प्रकाशन, नागपुर, पृ. 102।

6. कीर, ध. (1971), *लोकमान्य तिलक: आधुनिक भारत के निर्माता*. पॉपुलर प्रकाशन, बंबई, पृ. 175।
7. त्रिपाठी, अ. (1967), *द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज: इंडियाज नेशनल मूवमेंट*. अलाइड पब्लिशर्स, कलकत्ता, पृ. 128।
8. देसाई, ए. आर. (2013), *भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि*. पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई, पृ. 245।
9. प्रधान, प्र. प्र., व भागवत, ए. क. (1959), *लोकमान्य तिलक: एक जीवनी*. जयको पब्लिशिंग हाउस, बंबई, पृ. 340।
10. वर्मा, व. प्र. (1992), *आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन*. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, पृ. 192।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2020), *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 38।



EARN YOUR MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

R
S
E
A
R
C
H
G
A
T
E
W
A
Y

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



A
R
O
G
Y
A
M
O
N
L
I
N
E

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER



COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



- BLUE** Calms your Child's Mind & Body
- YELLOW** Promotes Concentration, Stimulates the Memory
- PINK** Evokes Empathy, makes your Child Calm
- RED** Excites and energizes your Child's body
- GREEN** Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com



Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE